(b) The Government is following a liberalized policy for development of telecommunications facilities in rural backward villages.

(c) The norms as per the policy are given in the Statement laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT-8595/84).

(d) The Expenditure on Telecommunication Development for urban and Rural area is not accounted for separately. However the expenditure on Telephone Districts which are wholly for urban areas and for the circles which are mostly Rural is indicated below :

(Fig. in crores of Rs.)

	Expenditure during 1982-83	Expenditure during 1983-84 (Final Grant)
Territorial Telecom. Circles as a whole.	256.27	187.30
Telephone Distts. as a whole.	227.18	332.36
Functional Circles whose activities benefit circles as well as District.	72.13	114-94

टी. वी. लाइसेंस शुल्क का समाप्त किया जाना

3402. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टी. वी. का वार्षिक लाइसेंस शुल्क क्या है और क्या गाँवों में टेलीविजन की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुये सरकार का टी वी. लाइसेंस शुल्क कम अथवा समाप्त करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : टी. वी. सैटों का वार्षिक लाइसेंस शुल्क इस प्रकार है :-

घरेलू :	50.00 रुपये
सामुदायिक/ स्कूल/अस्पताल :	10.00 रुपये
वाणिज्यिक :	100.00 रुपये
प्रदर्शन :	50.00 रुपये
विक्रेता :	60.00 रुपये

टी. वी. सैटों के लाइसेंस शुल्क को कम/समाप्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Lack of Medical Facilities for Bidi Workers in Sanawat City

3403. SHRI SUBHASH YADAV : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of Government that there is lack of medical facilities for the Bidi workers working in Sanawat City of Khargone District of Madhya Pradesh ;

(b) if so, whether Central Government propose to open a Hospital from the Central Government funds to provide medical facilities to those bidi workers for the improvement of their health ;

(c) if so, the time by which a Hospital will be opened ; and

(d) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : (a) to

(d) According to the information available there are about 900 bidi workers in Khargone District and as such, there is no proposal to establish any Hospital at Sanawat City.

कैलो परियोजना के अंतर्गत कोयला खानों में अन्वेषणात्मक छिद्रण (ड्रिलिंग) कार्य का प्रस्ताव

3404. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कैलो परियोजना के अंतर्गत अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य आरंभ करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 5 दिसम्बर, 1983 को मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०/भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को रामगढ़ जिले में कोयला भंडारों की खोज के लिये समन्वेषी ड्रिलिंग कार्य शुरू करने के निर्देश दिये जायें ताकि मध्य प्रदेश सरकार अपनी कैलो सिंचाई परियोजना सरकार अपनी कैलो सिंचाई परियोजना पर काम कर सके । परन्तु बाद में वे. को. लि./भा. भू. स. ने यह सूचित किया कि 27 दिसम्बर, 1983 को राज्य सरकार के साथ हुई बैठक के फलस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार के खान और भूतत्व निदेशालय ने, भा० भू० स० के कोयला स्कन्ध के अधीन क्षेत्र में कोयला भंडारों के निर्धारण के लिये कैलो परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में अपनी दो रिग पहले ही लगा दी हैं ।

मध्य प्रदेश को कोयले/कोक की सप्लाई

3405. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को, राज्य की कोयला/कोक की वार्षिक सप्लाई में वृद्धि करने संबंधी एक प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां । मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्य उद्योग और खनिज साधन मंत्री ने एक पत्र लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश के लिये रेलवे के वैगन आबंटन की जो संख्या निश्चित की है वह अपर्याप्त है । पत्र में यह भी कहा गया था कि औद्योगिक उपभोक्ताओं बिशेषकर कटनी-मेहर बेल्ट के उपभोक्ताओं को पर्याप्त कोयला नहीं मिल रहा है ।

(ख) इस मामले की जांच की गई थी और मध्य प्रदेश वाणिज्य, उद्योग और खनिज साधन मंत्री को उत्तर भेजा गया था जिसमें यह बताया गया था कि रेलवे ने वैगन संख्या को बढ़ाकर 1983 जितना ही कर दिया है । तथा वैगनों की संख्या में और वृद्धि केवल रेल मंत्रालय ही कर सकता है । पत्र में यह भी बताया गया था कि कोलियरियों से रेल द्वारा सीधे प्रेषण के अलावा कोल इंडिया लि0 स्व-प्रेषित रेकों के जरिये कटनी, को कोयला भेजता रहा है ताकि कटनी, सतना और मैहर के उपभोक्ताओं की माँग पूरी की जा सके । इसके अलावा कोल इंडिया लि० रेल प्रेषण में रहने वाली कमी का